{2016} 8 एस.सी.आर. 394

महावीर सिंह

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य

आपराधिक अपील संख्या 1141/2007

09 नवम्बर, 2016

{ए.के. सिकरी एवं एन.वी. रमना, जे.जे.}

दंड संहिता, 1860- धारा 302- अपीलार्थी अभियुक्त के साथ अन्य सहअभियुक्त को अंतर्गत धारा 302, 147, 148 और 149 आई.पी.सी. का आरोप लगाया- विचारण न्यायालय ने अभियोजन गवाहन के प्रत्यक्षदर्शी एवं चिकित्सीय साक्ष्य के बीच विरोधाभासी बयानों, गवाहों के बयान दर्ज करने में देरी, उचित स्थल योजना की अनुपलब्धता और प्रमाणित बैलिस्टिक विशेषज्ञ की रिपोर्ट के अभाव में सभी अभियुक्तों को बरी कर दिया। राज्य की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी अभियुक्त को धारा 302 आईपीसी में दोषी ठहराया -अपील पर, अभिनिर्धारित किया गयाः मामले के तथ्यों में उच्च न्यायालय के लिए बरी किए जाने के आदेश में हस्तक्षेप करना कोई सम्मोहक और

सारगर्भित कारण नहीं था, क्योंकि अभियोजन पक्ष बुरी तरह से अभियुक्त के अपराध को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा- मात्र बंदूक और गोलियों की जब्ती, पक्षों के बीच दुश्मनी, और प्रतिद्वंदी समूहों के बीच बहस और गरमा गरम शब्दों का आदान- प्रदान उचित संदेह से परे अपराध को स्थापित नहीं कर सकता है-अपीलार्थी अभियुक्त को बरी किया गया

आपराधिक विचारण- विरोधाभासी बयान- अभिनिर्धारित: समय अंतराल के कारण मनुष्यों के लिए अलग-अलग बयान देना स्वाभाविक है- लेकिन अगर बयान अभियोजन पक्ष के मामले को विफल करते हैं, तो इस तरह के विरोधाभासी सामग्री को अदालत को सावधानीपूर्वक ध्यान रखना होगा।

बयान- प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य की तुलना में चिकित्सीय साक्ष्य- अधिक प्रामाणिक है। चिकित्सीय साक्ष्य की तुलना में प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य का अधिक साक्ष्यात्मक मूल्य है - लेकिन जब चिकित्सा साक्ष्य मौखिक गवाही को असंभव बनाता है, तो प्रत्यक्षदर्शी को अस्वीकार किया जा सकता है।

गवाहः हितबद्ध गवाह.साक्ष्य मूल्य- हितबद्ध गवाह की साक्ष्य की अत्यंत सावधानी के साथ जांच की जानी चाहिए- इस पर केवल तभी भरोसा किया जा सकता है, जब साक्ष्य में विश्वसनीयता, भरोसेमंदता एवं सच्चाई हो- एक हितबद्ध साक्ष्य की विरोधाभासी गवाही को आम तौर पर निर्णायक नहीं माना जा सकता है।

संयोग गवाह- प्रमाणिक मूल्य- हालांकि संयोग गवाह की साक्ष्य स्वीकार्य है, फिर भी ऐसे गवाह को घटना के स्थान पर अपनी उपस्थिति को उचित रूप से बताना होगा।

अपील- बरी किए जाने के खिलाफ अपील- अभिनिर्धारित: अपीलीय न्यायालय को तथ्यों के साथ-साथ कानून पर भी साक्ष्य की समीक्षा करने, पुनः मूल्यांकन करने और पुनर्विचार करने की की शक्तियों पर कोई बंधन नहीं हैं लेकिन न्यायालय को अपील में हस्तक्षेप करने में सतर्क रहने की आवश्यकता है जब तक कि बरी करने के आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए ठोस व पर्याप्त आधार न हों।

जाँच- जाँच अधिकारी- हत्या के मामले से निपटने के लिए अपने दृष्टिकोण में मेहनती, सच्चा और निष्पक्ष होना अपेक्षित है- उसका प्रदर्शन हमेशा पुलिस नियमावली के अनुरूप होना चाहिए -एक दोष और कर्तव्य का उल्लंघन अभियोजन मामले के लिए घातक साबित हो सकता है।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

1.1 आपराधिक न्यायशास्त्र में, एक अभियुक्त जब तक उसे पूर्ण सुनवाई के बाद एक सक्षम अदालत द्वारा दोषी नहीं ठहराया जाता है, तब तक उसे निर्दोष माना जाता है, और एक बार जब निचली अदालत ठोस तर्क से आरोपी को बरी कर देती है, तो उसकी पुष्टि की जाती है। निर्दोषता अपील पर विचार करते समय अपीलीय न्यायालय पर अधिक बोझ डालती

है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि, यह तय कानून है कि बरी करने के आदेश में तथ्यों और कानून दोनों पर साक्ष्य की समीक्षाए पुनर्मूल्यांकन और पुनर्विचार करने के लिए अपीलीय न्यायालय की शक्ति पर कोई बंधन नहीं हैं, लेकिन अदालत को बरी करने के आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए सावधानी बरतें, जब तक दोषमुक्ति के आदेश में बाध्यकारी और पर्याप्त आधार न हों। अपीलीय अदालत को इस तरह के मामलों में आदेश पारित करते समय स्पष्ट कारण के साथ निष्कर्ष निकालना होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अपीलीय न्यायालय किन परिस्थितियों में दोषमुक्ति के आदेश में हस्तक्षेप कर सकता है, जिसके संबंध में कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं हो सकता है, लेकिन यह प्रत्येक मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर निर्भर करता है। {पैरा 12, 13} {403- ई-एच}

1.2 वर्तमान मामले में, तथ्यों के एक ही समूह से, विचारण न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय भी अलग-अलग निष्कर्षों पर पहुंचे हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा निष्कर्ष अपील में ऐसी कवायद तब तक नहीं की जा सकती जब तक कि निचली अदालत द्वारा निकाले गए निष्कर्ष को तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर कायम नहीं रखा जा सकता है और जब रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर दो निष्कर्ष संभव हैं तो अपीलीय अदालत को निचली अदालत द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने के लिए और अधिक अनिच्छुक होना चाहिए। {पैरा15} {404 एफ-जी}

2. नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों ने एक आम राय बनाई कि अभियोजन पक्ष सहअभियुक्त के खिलाफ आई.पी.सी. की धारा 148 और 302/149 के तहत आरोप साबित करने में विफल रहा है और उसे आरोपमुक्त कर दिया गया है। विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय के बीच असहमति केवल अपीलकर्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत आरोप के संबंध में है अपीलकर्ता ने वह अपराध किया है या नहीं, जिसके लिये उस पर आरोप लगाया गया है, यह तय करने में नीचे की अदालतों के बीच मतभेद मुख्य रूप से घटनास्थल पर कथित प्रत्यक्षदर्शियों की उपस्थिति, अपीलकर्ता द्वारा मृतक को आग्नेयास्त्र से चोट पहुंचाने की संभावना के ईर्द गिर्द घूमता है। मृतक को लगी चोट की स्थिति, भौतिक दुर्बलता यदि कोई हो, और नेत्र संबंधित और चिकित्सकीय साक्ष्य में विरोधाभास {पैरा 16,23}, {404-एच 405-ए-बी, 407-जी-एच 408-ए}

3. हालाँकि, शुरुआत में, आरोपी/अपीलकर्ता ने आरोप को पूरी तरह से खारिज कर दिया और बचाव में यह बहाना लेकर खुद को दोषी नहीं बताया कि घटना की तारीख पर, वह अपने खेत की सिंचाई कर रहा था, लेकिन उसके दावे का किसी भी सबूत से समर्थन नहीं किया गया है। { पैरा 16} {405-बी}

4. माना जाता है कि पार्टियां शत्रुतापूर्ण शर्तों पर है और विचाराधीन घटना मृतक के निवास पर दिन के उजाले में हुई। अभियोजन पक्ष ने,

अपने संस्करण के समर्थन में चश्मदीदों पी डब्ल्यु 7, पी डब्ल्यु 8, पी डब्ल्यु 9 व पी डब्ल्यु 11 के बयानों पर बहुत अधिक भरोसा किया है। निचली अदालत के न्यायाधीश बयानों की देरी से रिकॉर्डिंग के मध्य नजर मौके पर चश्मदीदों की उपस्थिति पर अविश्वास किया। जांच अधिकारी यह बताने में असफल रहे कि मृतक को गोली कहां लगी थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट में कहीं भी घटना के गवाह के रूप में प्रत्यक्षदर्शी पी डब्ल्यु 8 का नाम या उपस्थिति का उल्लेख नहीं किया गया था। {पैरा 17} {405-डी-एफ}

5. उच्च न्यायालय ने पीडब्लू 9 के साक्ष्य को काफी महत्व दिया है, जिसने स्वीकार किया है कि वह मृतक के लिए आरोपी के खिलाफ एक अन्य मामले में गवाह रहा है। इस प्रकार पीडब्लू 9 परिवार के लिए एक पॉकेट गवाह के रूप में कार्य कर रहा है। इसके अलावा, इस स्वतंत्र गवाह की विश्वसनीयता को इस तथ्य पर चुनौती दी जा सकती है कि हंगामा केवल पीडब्लू 9 द्वारा सुना गया था, जबकि इलाके के बाकी सदस्य मदद के लिए नहीं आए थे। पीडब्लू 9 द्वारा यह स्वीकारोक्ति न केवल न्यायालय को अपने बयान की सत्यता पर संदेह करने के लिए मजबूर करता है, बल्कि पीडब्लू 7 के इस कथन पर भी संदेह पैदा करता है। चूँकि पीडब्लू 9 एक मौका गवाह होने के साथ.साथ एक इच्छुक गवाह भी है, इसलिये यह संदेह का कारण बनता है और विश्वास को प्रेरित नहीं करता है। इच्छुक गवाह के साक्ष्य की अत्यंत सावधानी से जांच की जानी चाहिए। इस पर

तभी भरोसा किया जा सकता है जब साक्ष्य में सच्चाई हो, ठोस, विश्वसनीय और भरोसेमंद हो। एक इच्छुक गवाह की विरोधाभासी गवाही को आमतौर पर इस रूप में निर्णायक नहीं माना जा सकता है। हालांकि मौका गवाह का साक्ष्य भारत में स्वीकार्य है, फिर भी मौका गवाह को उस विशेष बिंदु पर उपस्थिति के बारे में तर्क संगत रूप से समझना पडता है, खासकर तब जब उसके बयान पर दागी होने का आरोप लगाया जा रहा हो। {पैरा 18,19} {405- एफ-एच, 406-ए-सी}

6. पीडब्लू 12 के साक्ष्य से पता चलता है कि जब मृतक को गोली लगी थी, तो वह खड़े होने की स्थिति में था और गोली शरीर के बाईं ओर से प्रवेश कर शरीर के दाईं ओर से बाहर निकल गई होगी। हालाँकि, इस तथ्य की पुष्टि पीडब्लू 7 और पीडब्लू 8 के साक्ष्यों से होती है, लेकिन पीडब्लू 9 और पीडब्लू 11 के बयान इसका समर्थन नहीं करते हैं। इसी प्रकार, पी डब्ल्यु 12 और प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों के बीच विरोधाभास थे कि मृतक को गंभीर चोट पहुंचाने के दौरान हमलावर की दूरी और उंचाई क्या थी और क्या मृतक मंच (चबूतरा) पर खडा था या उससे नीचे आया था। गोली लगने से घायल हो गए। पी डब्लयु 12 यह बताने के लिए स्पष्ट और निश्चित नहीं था कि हमलावर ने किस स्थिति और दूरी से बंदूक चलाई होगी।{पैरा 20} {406-डी-एफ}

7. अपीलार्थी के पास से एक बंदूक 12 जिंदा और 9 खाली कारतुस बरामद किए गए। बैलिस्टिक विशेषज्ञ की रिपोर्ट से अभियोजन की कहानी कुछ हद तक मजबूत हुई है, परंतु कहीं भी यह उल्लेख नहीं किया गया कि पीडित की मृत्यु जब्त बंदूक से निकली गोली से हुई। केवल बंदूक जब्ती और कारतूस अपीलार्थी की ओर से विभिन्न आपराधिक मुकदमों के कारण पक्षों के बीच चल रही शत्रुता और उसी दिन सुबह प्रतिद्वंद्वी समूहों के बीच बहस और गरमागरम शब्दों का आदान-प्रदान अभियुक्त के अपराध को उचित संदेह से परे स्थापित नहीं कर सकता है। {पैरा 21} {406.जी.एच} {407.ए.बी}

8. यद्यपि गवाह की आंखों की गवाही का चिकित्सीय साक्ष्य की तुलना में अधिक साक्ष्य मूल्य होता है, जब मेडिकल साक्ष्य नेत्र संबधी गवाही को असंभव बना देता है, जो साक्ष्य के मूल्यांकन की प्रक्रिया में एक प्रासंगिक कारक बन जाता है। हालांकि जहां चिकित्सीय साक्ष्य इतना दूर चला जाता है कि यह नेत्र संबंधी साक्ष्य के सत्य होने की सभी संभावनाओं को पूरी तरह से खारिज कर देता है, वहां नेत्र संबंधी साक्ष्य पर अविश्वास किया जा सकता है। {पैरा 22} {407.सी.डी}

अब्दुल सईद बनाम एम. पी. राज्य 2010 {13} एस. सी. आर. 311 {2010} 10 एस. सी. सी. 259- पर विश्वास

9. यह सर्वोच्च न्यायालय का कर्तव्य है कि वह बयानों की उथल-पुथल से सच्चाई को निकाले और मनुष्यों के लिए समय अंतराल के कारण अलग-अलग बयान देना स्वाभाविक है, लेकिन अगर इस तरह के बयान अभियोजन पक्ष के मूल को विफल करते हैं तो ऐसे विरोधाभास विद्यमान हैं और अदालत को ऐसे बयानों का ध्यान रखना होगा। उक्त प्रकरण में उपस्थित इस मामले में अतिशयोक्ति और विरोधाभास हैं, जो सामान्य परिस्थितियों में अनिवार्य रूप से संदेह पैदा करते हैं {पैरा 24} {408.बी.सी}

तहसीलदार सिंह बनाम यू पी राज्य, ए आई आर 1959 एस सी 1012: 1959 पूरक एस सी आर 875 पुधु राजा बनाम राज्य 2012 {8} एस सी आर 740 ; {2012} 11 एस सी सी 196: यू पी राज्य बनाम नरेश ; {2011} 4 एस सी सी 324- पर विश्वास

10. हत्या के मामले की जांच कर रहे जाँच अधिकारी से यह उम्मीद की जाती है कि वह अपने दृष्टिकोण में मेहनती, सच्चा और निष्पक्ष होगा और उसका प्रदर्शन हमेशा पुलिस नियमावली के अनुरूप होना चाहिए और चूक या कर्तव्य का उल्लंघन उसके लिए घातक साबित हो सकता है। वर्तमान मामले में, अभियुक्त के अपराध को सिद्ध करने के लिए की गई जांच बिना किसी चिंता के और बिना किसी उत्साहजनक प्रदर्शन के साथ

की गई थी, जिसमें आवश्यक उत्साह और भावना के साथ कोई दृढ़ और ईमानदार प्रयास नहीं था। {पैरा 26} {408 -एफ-जी}

11. उच्च न्यायालय के पास अभियुक्त को बरी करने के आदेश में हस्तक्षेप करने हेतु कोई बाध्यकारी ठोस कारण नहीं हैं कि जब अभियोजन पक्ष दोष स्थापित करने में बुरी तरह विफल रहा है अभियुक्त पहले ही नौ साल के कारावास से गुजर चुका है और इसलिए यह इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप को आमंत्रित करने वाला एक उपयुक्त मामला है। {पैरा 26} {408 -एच, 409-ए}

केस कानून संदर्भ

2010 (13) एससीआर 311 पैरा 22 पर भरोसा

1959 पूरक एससीआर 875 पैरा 24 पर भरोसा

2012 (8) एससीआर 740 पैरा 24 पर भरोसा

2011 (15) एससीआर 34 पैरा 24 पर भरोसा

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील सं 1141/2007

एम. पी. उच्च न्यायालय ग्वालियर के सरकारी अपील सं. 36/96 में पारित आदेश और निर्णय दिनांकित 19.03.2007 से।

अनुराग दुबे, सुश्री अनु साहनी, सुश्री मीनाक्षी पी, एस. आर. सेटिया अधिवक्तागण अपीलार्थी की ओर से।

सी. डी. सिंह, सुश्री साक्षी कक्कड़, डी. एस. परमार, संदीपन, अधिवक्तागण प्रतिवादी की ओर से।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया।

एन. वी. रमना जे.

1. यह अपील मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, ग्वालियर की पीठ द्वारा आपराधिक अपील संख्या 36/1996 में 19 मार्च, 2007 को पारित किये गये आदेश से उत्पन्न होती है, जिसके तहत उच्च न्यायालय ने राज्य द्वारा की गई अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया है, जिसके तहत अपीलार्थी को धारा 148 आई.पी. सी. और आई. पी. सी. की धारा 307 अपराध के लिए दोषी ठहराया गया एवं उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

2. अभियोजन पक्ष के मामले से यह तथ्य उद्धृत किया गया कि दिनांक 26.12.1987 को दोपहर 1 बजे जब गंभीर सिंह; (पीडब्लू 7) मृतक का भाई अपने घर पर दोपहर का भोजन कर रहा था। अपीलार्थी सह-अभियुक्त व्यक्तियों के एक समूह के साथ घातक हथियारों से लैस होकर गाली-गलौज करते हुए उसके घर में घुस गये अपने भाई जगन्नाथ सिंह (मृतक) अपने भतीजे बीर सिंह (पीडब्लू 11) के साथ बैठा था। जब जगन्नाथ सिंह (मृतक) ने उनके व्यवहार पर आपत्ति जताई अपीलार्थी ने

मृतक के पेट पर गोली चला दी, जिसके परिणामस्वरूप वह जमीन पर गिर गया और चोटों के कारण उसकी मौत हो गई।

3. गंभीर सिंह (पीडब्लू 7) उसी दिन शाम 4.15 बजे मृतक के शव को बैलगाड़ी पर लाद कर पुलिस स्टेशन ले गया और प्राथमिकी दर्ज कराई, जो (अनुलग्नक पी -1) है। दिलीप सिंह यादव (पीडब्लू-13) ने जांच ज्ञापन तैयार किया और डॉ. ए. के. उपाध्याय (पीडब्लू 12) ने शव का पोस्टमार्टम किया। जब्ती ज्ञापन के अनुसार, अगले दिन दिलीप सिंह यादव (पीडब्लू-13) ने घटना स्थल से खून से सनी मिट्टी और सादे मिट्टी को जब्त किया उसने अपीलार्थी महावीर सिंह के कब्जे से एक बंदूक, 12 जिंदा कारतुस और 9 खाली कारतुस भी जब्त किए, शोभाराम सहअभियुक्त के कब्जे से एक कुल्हाडी, और कन्छेद सिंह ( अन्य सह-अभियुक्त) के कब्जे से एक लाठी जब्त की और ज्ञापन के अनुसार उन्हें सागर फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में भेज दिया। नतीजतन, गवाहों के बयान सीआरपीसी की धारा 161 के तहत दर्ज किए गए, स्पॉट मैप तैयार किया गया और आरोप पत्र तैयार किया गया। अपीलार्थी के खिलाफ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, लहार के न्यायालय में अपीलार्थी के विरूद्ध आ.पी.सी. की धारा 302, 148 और सहअभियुक्तो के विरूद्ध आईपीसी की धारा 149 के तहत आरोप तय किये गये जिन्होंने खुद को निर्दोष बताया और अन्वीक्षा चाही और मामला सत्र न्यायालय को सौंप दिया। अभियुक्त के अपराध को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने 13 गवाहों से पूछताछ की है और कई दस्तावेजों

को प्रदर्शित करवाया है, जबकि अभियुक्त से बचाव में किसी से भी पूछताछ नहीं की गई है और उसकी ओर से कोई दस्तावेज प्रदर्शित नहीं किया गया है।

4. विचारण न्यायालय ने अपने 30 नवंबर, 1994 के निर्णय और आदेश द्वारा इस आधार पर अपीलार्थी को मुख्य रूप से कथित अपराधों से बरी कर दिया कि प्रत्यक्षदर्शियों एवं चिकित्यकीय साक्ष्य में विरोधाभास हैं, अभियोजन पक्ष इससे आगे साबित करने में विफल रहा है अपीलार्थी ने मृतक को जान से मार देने के उद्देश्य से गैरकानूनी रूप से एकत्रित हुए एवं ये भी नहीं सिद्ध कर पाये कि गोली अपीलार्थी से जब्त की गई बन्दूक से चलाई गई थी।

5. विचारण न्यायालय के निर्णय से असंतुष्ट राज्य ने उच्च न्यायालय के समक्ष यह दावा करते हुए एक अपील दायर की कि विचारण न्यायालय का निर्णय विकृत और अवैध है क्योंकि उसने अभियोजन पक्ष के सबूतों की सही परिप्रेक्ष्य में विवेचना नहीं की और चश्मदीदों के सबूतों को नजरअंदाज कर दिया। उच्च न्यायालय ने साक्ष्य अभियोजन पक्ष के गवाहों और रिकॉर्ड पर उपलब्ध अन्य सामग्री के पुन:विश्लेषण से इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि विचारण न्यायालय ने अन्य सहआरोपियों को बरी करने में सही किया था लेकिन आईपीसी की धारा 302 के तहत अपीलकर्ता को बरी करने में गलती पाई। इसलिए उच्च न्यायालय ने धारा 148 के तहत आरोप

के संबंध में विचारण न्यायालय के फैसले की पुष्टि करते हुए अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया और अपीलकर्ता को धारा 302 आईपीसी के तहत अपराध के लिये दोषी ठहराया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अपीलकर्ता ने अपील में उच्च न्यायालय के फैसले से व्यथित होकर इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

6. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि विचारण अदालत ने रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों पर विचार करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचने पर अपीलार्थी को बरी कर दिया कि अभियोजन पक्ष के गवाहों की गवाही में विश्वसनीयता की कमी है और विशेष रूप से चिकित्सा और प्रत्यक्षदर्शी गवाही परस्पर विरोधी है कथित चश्मदीदों के साक्ष्य दर्ज करने में जांच अधिकारी की ओर से काफी देरी हुई यहां तक कि घटना के दिन किसी भी चश्मदीद का बयान दर्ज नहीं किया गया था।

7. इस तथ्यात्मक मैट्रिक्स की पृष्ठभूमि में, अपीलकर्ता के लिए विद्वान वकील ने अपने तर्क आगे बढ़ाए हैं कि चूंकि अपीलकर्ता और पीड़ित पक्षों के बीच कुछ लंबित आपराधिक मामलों पर पूर्व दुश्मनी है, इसलिए मृतक के परिवार के सदस्य, यानी गंभीर सिंह (पीडब्लू 7), शांति देवी (पीडब्लू 8), बीर सिंह (पीडब्लू 11) ने मिलीभगत करके और एक पॉकेट गवाह माधो सिंह (पीडब्लू 9) की मदद से खुद को प्रत्यक्षदर्शी के रूप में पेश करके कहानी गढ़ी और अपीलकर्ता को झूठा फंसाया। उनके अनुसार,

यह तथ्य चिकित्सीय साक्ष्यों में विरोधाभासों और कथित इच्छुक प्रत्यक्षदर्शी के अविश्वसनीय साक्ष्यों से स्पष्ट रूप से स्थापित होता है। घटना के समय गंभीर सिंह (पीडब्लू 7) की उपस्थिति, जैसा कि अभियोजन पक्ष द्वारा काफी हद तक भरोसा किया गया था, बीर सिंह (पीडब्लू 11) के साक्ष्य के प्रकाश में झूठी साबित होती है, जिसने अपनी गवाही में कहीं भी उल्लेख नहीं किया कि गंभीर सिंह (पीडब्लू 7) अकेले घर से बाहर आया और घटना देखी और माधो सिंह (पीडब्लू 9) ने दावा किया कि गोलीबारी के तुरंत बाद, गंभीर सिंह (पीडब्लू 7), बीर सिंह (पीडब्लू 11) और शांति देवी (पीडब्लू 8) घर से बाहर आए और इसलिए आरोपी मौके से भाग गए। यह भी तर्क दिया गया है कि कथित प्रत्यक्षदर्शी गंभीर सिंह (पीडब्लू 7), बीर सिंह (पीडब्लू 11) और शांति देवी (पीडब्लू 8) अभियोजन के मामले को मेडिकल रिपोर्ट से जोड़ने के लिए अदालत के समक्ष अपनी गवाही में भौतिक सुधार किए। ऐसे में घटना स्थल पर चश्मदीदों की मौजूदगी संदिग्ध है।

8. विद्वान वकील का यह भी कहना है कि जांच अधिकारी द्वारा तैयार की गई साइट योजना और चिकित्सा साक्ष्य के अनुसार मृतक जगन्नाथ सिंह खड़े थे जब उन्हें गोली मार दी गई थी। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक, मृतक को लगी चोटें तभी संभव हैं जब हमला करने वाला पीड़ित से ऊंचाई पर खड़ा हो। इसके विपरीत, कथित प्रत्यक्षदर्शी के साक्ष्य के साथ अभियोजन पक्ष द्वारा आगे बढ़ाया गया मामला यह है कि अपीलकर्ता

निचले स्तर पर खड़ा था और मृतक उच्च स्तर पर यानी मंच पर खड़ा था। अपने बयान में माधो सिंह (पीडब्लू 9) ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया कि मृतक चबूतरे पर बैठा था और अपीलकर्ता जमीन पर खड़ा था, जब उसे गोली मारी गई। जबकि मेडिकल रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि घावों के किनारे उलटे थे और गोली 6 फीट की दूरी से चलाई गई होगी, और प्रत्यक्ष प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही के अनुसार, उक्त दूरी 12 से 22.5 फीट के बीच थी। घटना के कथित स्थान यानी मंच पर मानव रक्त की अनुपस्थिति और मंच के सामने जमीन पर रक्त की उपस्थिति अभियोजन पक्ष के मामले को और भी अधिक संदिग्ध बना देती है। इस खून का मिलान भी मृतक के खून से नहीं किया जा सका, इसलिए हथियारों की बरामदगी का कोई मतलब नहीं है, केवल इस कारण से कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि मृतक की मृत्यु एक ही बंदूक की गोली के कारण हुई थी, और अपीलकर्ता के पास से नौ खाली कारतूसों की बरामदगी किसी भी तरह से उसे अपराध से नहीं जोड़ती है, जबकि घटना के स्थान से खाली कारतूस बरामद नहीं हुए थे और प्रमाणित सबूत के अभाव में भी कि मृतक को गोली अपीलकर्ता के स्वामित्व वाली बंदूक से मारी गई थी। विद्वान वकील का कहना है कि प्रत्यक्षदर्शी के बयान भरोसेमंद नहीं हैं। संपूर्ण तथ्यों पर विचार करते हुए, जैसे चश्मदीदों के बयानों की देरी से रिकॉर्डिंग और यह बताने का असफल प्रयास कि गोली पीड़ित को कहाँ लगी थी और अभियोजन पक्ष के गवाहों और मेडिकल विशेषज्ञ के बयानों में विरोधाभाषी

बयानों के आधार पर विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता को बरी करने का आदेश दिया।

9. विद्वान वकील ने अंतत प्रस्तुत किया कि दूसरी ओर उच्च न्यायालय सही कानूनी परिप्रेक्ष्य में सबूतों की विवेचना करने में विफल रहा और एक ठोस और विस्तृत तर्क के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा पारित बरी करने के सुविचारित फैसले में गलत तरीके से हस्तक्षेप किया और उच्च अदालत ने आईपीसी की धारा 302 के तहत अपराध के लिए आरोपी को दोषसिद्ध करके गंभीर गलती की। आक्षेपित निर्णय स्थापित कानूनी सिद्धांतों के विपरीत है क्योंकि इसमें चिकित्सा साक्ष्य को उचित महत्व नहीं दिया गया और बिना कोई कारण बताए इसे खारिज कर दिया गया। इस प्रकार, विचारण न्यायालय द्वारा पारित बरी करने के तर्कसंगत फैसले में उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप अनुचित है। विद्वान वकील का कहना है कि स्थापित कानूनी सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य में, उच्च न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता को दोषी ठहराया जाना अस्पष्ट और अनावश्यक है और इसे इस न्यायालय द्वारा रद्द करने की आवश्यकता है।

10. दूसरी ओर, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने तर्क दिया कि अपीलकर्ता को बरी करने का विचारण न्यायालय का निर्णय पूरी तरह से गलत था क्योंकि इसे अभियोजन साक्ष्य को उसके सही परिप्रेक्ष्य में ध्यान में रखे बिना पारित किया गया था। चश्मदीदों के साक्ष्यों में कोई

असंगति नहीं थी जो अपराध स्थल पर मौजूद थे और विचारण न्यायालय द्वारा उनके साक्ष्यों को नजरअंदाज करना उचित नहीं था। उच्च न्यायालय ने, रिकॉर्ड पर मौजूद सभी साक्ष्यों की फिर से सराहना करते हुए एक सुविचारित निर्णय द्वारा आईपीसी की धारा 302 के तहत आरोपी को दोषी ठहराने में उचित रुख अपनाया और कहा कि हस्तक्षेप का आह्वान करने वाले आरोपी की सजा में कोई अवैधता या विकृति नहीं है।

11. हमने दोनों पक्षों के विद्वान वकीलों को विस्तार से सुना है और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया है। बरी किए जाने के आदेश के खिलाफ अपील में अपीलीय अदालत के हस्तक्षेप के दायरे पर गौर करना जरूरी है और उच्च न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय द्वारा पारित बरी करने के आदेश को पलटकर आईपीसी की धारा 302 के तहत आरोपी को दोषी ठहराना उचित था।

12. आपराधिक न्यायशास्त्र में, एक आरोपी को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि उसे पूर्ण सुनवाई के बाद सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहराया जाता है, और एक बार जब विचारण न्यायालय ठोस तर्क द्वारा आरोपी को बरी कर देता है, तो उसकी बेगुनाही की पुनः पुष्टि अपील पर विचार करते समय अपीलीय न्यायालय पर अधिक बोझ डालती है। इसमें कोई संदेह नहीं है, यह स्थापित कानून है कि तथ्यों और कानून दोनों के आधार पर साक्ष्य की समीक्षा, पुनर्मूल्यांकन और पुनर्विचार करने की

अपीलीय अदालत की शक्ति पर कोई बाधा नहीं है, जिस पर बरी करने का आदेश पारित किया गया है, लेकिन अदालत को अपील में हस्तक्षेप करते समय बहुत सतर्क रहना होगा जब तक कि बरी करने के आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए बाध्यकारी और पर्याप्त आधार न हों। अपीलीय न्यायालय को आदेश पारित करते समय ऐसे निष्कर्ष के लिए स्पष्ट तर्क देना होता है।

13. इसमें कोई संदेह नहीं है कि कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं हो सकता है कि किन परिस्थितियों में अपीलीय अदालत बरी करने के आदेश में हस्तक्षेप कर सकती है, लेकिन यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। मौजूदा मामले में, हमें अभियुक्तों को दोषी ठहराने के उच्च न्यायालय के निष्कर्ष के पीछे के तर्क और विचारण न्यायालय द्वारा पारित बरी करने के आदेश से विचलित होने के अनिवार्य कारणों की जांच करनी होगी।

14. दिए गए फैसले का गहन विश्लेषण करने पर, यह स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को आंशिक रूप से रद्द करने के लिए कोई कारण दर्ज नहीं किया है, जिसने सभी आरोपी व्यक्तियों को उसके समक्ष समान तथ्यों के आधार पर बरी कर दिया है। उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय के बरी करने के आदेश को रद्द कर दिया है और कहा है कि विचारण न्यायालय ने अपना तर्क अनुमान के आधार पर दिया

है। हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय ने भी वही गलती की है और उन्हीं तथ्यों और अनुमान के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अपीलकर्ता दोषी है।

15. अपीलकर्ता के विद्वान वकील द्वारा विशेष रूप से आग्रह किया गया है कि चिकित्सा साक्ष्य के अनुसार, मृतक को लगी चोटें केवल तभी संभव हैं जब हमलावर पीड़ित से ऊंचाई पर खड़ा हो। इस प्रक्रिया में, अदालत ने अनुमान लगाया कि महावीर सिंह (अभियुक्त-अपीलकर्ता) और जगन्नाथ (मृतक) समान ऊंचाई पर थे, जो कि विवादित नहीं है और निष्कर्ष पर पहुंचने के लिये रिकॉर्ड पर कोई सबूत उपलब्ध नहीं है कि दोनों की ऊंचाई समान है। इस संबंध में रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य डॉ. ए.के. उपाध्याय (पीडब्लू 12) का बयान है कि मृतक औसत ऊंचाई का था। अब यह साबित करने के लिए कि गोली नीचे की ओर चली, उन्होंने बताया कि बंदूक की स्थिति छाती पर नीचे की और टीकी हुई थी। अब तार्किक भ्रांति यह है कि मंच की ऊंचाई मान ली गई है, जबकि जांच अधिकारियों की लापरवाही से की गई जांच के कारण मंच की उंचाई दर्ज नहीं की गई थी। इस तथ्य के कारण एक उचित संदेह मौजूद है कि मंच की ऊंचाई दर्ज नहीं की गई थी और इस समय इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, डॉक्टर के बयान से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि गोली चलाने वाला नीचे खडा रहा होगा। जबकि कुछ गवाहों ने बयान दिया है कि मृतक जमीन पर था, जबकि अन्य ने इस तथ्य की ओर इशारा किया है कि वह

मंच पर खड़ा था। इसलिए, समान तथ्यों के आधार पर विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय अलग-अलग निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, इस तरह अपील में तथ्यों, परिस्थितियों और रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर जब दो निष्कर्ष संभव हों, तो अपीलीय अदालत को विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने के लिए और अधिक अनिच्छुक होना चाहिए।

16. हमें ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता ने वह अपराध किया है या नहीं, जिसके लिए उस पर आरोप लगाया गया है, यह तय करने में विचारण न्यायालय के बीच मतभेद मुख्य रूप से घटनास्थल पर कथित प्रत्यक्षदर्शियों की उपस्थिति, अपीलकर्ता द्वारा बंदूक से चोट पहुंचाने की संभावना, मृतक को लगी चोट की स्थिति, भौतिक दुर्बलता, यदि कोई हो, और चश्मदीद एवं चिकित्सीय साक्ष्य में विरोधाभास के इर्द-गिर्द घूमता है। इससे यह स्पष्ट है कि आरोपी अपीलकर्ता ने आरोप से पूरी तरह से इन्कार कर दिया और अन्यत्र उपस्थिति का सहारा लेते हुए खुद को निर्दोष बताया कि, घटना की तारीख पर, वह अपने खेत की सिंचाई कर रहा था, लेकिन इस बचाव को किसी साक्ष्य द्वारा साबित नहीं किया गया।

17. निस्संदेह, गंभीर सिंह (पीडब्लू 7-मृतक का भाई) ने स्वीकार किया है कि आरोपी और उसके परिवार के सदस्यों के बीच कुछ आपराधिक कार्यवाही लंबित थीं। वह यह भी मानते हैं कि घटना से पहले ही आरोपियों

ने एक मामला दर्ज कराया था, जिसमें शांति देवी (पीडब्लू 8-मृतक की पत्नी) ने भी गवाही दी है कि उसके बेटे विजेंदर और ढुल्लू के बीच झगड़ा हुआ था, जिस पर उन्होंने उसके पति की हत्या कर दी। इस प्रकार, पक्षकारान निश्चित रूप से शत्रुतापूर्ण शर्तों पर हैं और विचाराधीन घटना मृतक के निवास पर दिन के उजाले में हुई, जिससे उसका बहुमूल्य जीवन खत्म हो गया। अभियोजन पक्ष ने, अपने मामले के समर्थन में, प्रत्यक्षदर्शी गंभीर सिंह (पीडब्लू 7-शिकायतकर्ता और मृतक का भाई), शांति देवी (पीडब्लू 8-मृतक की पत्नी), माधो सिंह (पीडब्लू 9) और बीर सिंह (पीडब्लू 11-मृतक का भतीजा) के बयानों पर बहुत अधिक भरोसा किया है विद्वान विचारणीय न्यायाधीश ने जांच अधिकारी (पीडब्लू 13) द्वारा उनके बयान दर्ज करने में देरी के कारण मौके पर चश्मदीद गवाहों की उपस्थिति पर अविश्वास किया और वे यह भी बताने में असफल रहे कि गोली मृतक को कहां लगी थी। हमने यह भी पाया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में कहीं भी घटना के गवाह के रूप में चश्मदीद शांति देवी (पीडब्लू 8) के नाम या उपस्थिति का उल्लेख नहीं किया गया था।

18. उच्च न्यायालय ने उक्त माधो सिंह (पीडब्लू 9) के साक्ष्य को बहुत महत्व दिया है क्योंकि वह एक स्वतंत्र गवाह है। रिकॉर्ड को देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त व्यक्ति पहले भी कई मौकों पर पीड़ित परिवार के लिए उसी आरोपी के खिलाफ गवाही दे चुका है। यह तथ्य होने के कारण, स्वतंत्र गवाह पर न्यायशास्त्र का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है। यह

स्थापित सिद्धांत है कि स्वतंत्र गवाह के साक्ष्य की अत्यंत सावधानी से जांच की जानी चाहिए। इस पर तभी भरोसा किया जा सकता है जब साक्ष्य ठोस, विश्वसनीय और भरोसेमंद हो। यहां हम मौका गवाह का भी उल्लेख कर सकते हैं। यह देखा जाना चाहिए कि यद्यपि एक मौका गवाह का साक्ष्य भारत में स्वीकार्य है, फिर भी मौका गवाह को उस विशेष बिंदु पर उपस्थिति के बारे में तर्कसंगत रूप से समझाना पड़ता है, खासकर तब जब उसके बयान पर दागी होने का आरोप लगाया जा रहा हो।

19. किसी इच्छुक गवाह की विरोधाभासी गवाही को आमतौर पर निर्णायक नहीं माना जा सकता है। उक्त माधो सिंह (पीडब्लू 9) ने स्वीकार किया है कि वह मृतक के आरोपियों के खिलाफ एक अन्य मामले में गवाह रहा है। यहां यह देखा जा सकता है कि उक्त माधो सिंह (पीडब्लू 9) परिवार के लिए पॉकेट गवाह के रूप में काम कर रहा है। इसके अलावा, इस स्वतंत्र गवाह की विश्वसनीयता को इस तथ्य पर चुनौती दी जा सकती है कि हंगामा केवल उक्त माधो सिंह (पीडब्लू 9) ने सुना था जबकि इलाके के बाकी सदस्य मदद के लिए नहीं आए थे। चूँकि माधो सिंह (पीडब्लू 9) एक मौका गवाह होने के साथ-साथ एक स्वतंत्र गवाह भी है, इसलिए यह संदेह पैदा करता है और विश्वास को प्रेरित नहीं करता है। माधो सिंह (पीडब्लू 9) की यह स्वीकारोक्ति न केवल हमें उसके स्वयं के बयान की सत्यता पर संदेह करने के लिए मजबूर करती है, बल्कि गंभीर सिंह (पीडब्लू 7) के कथनों पर भी संदेह पैदा करती है।

20. हमने विशेषज्ञ गवाहों के साथ-साथ अन्य प्रत्यक्ष गवाहों के साक्ष्यों की गहन जांच की है। डॉ. ए.के. उपाध्याय (पीडब्लू 12) के साक्ष्य से पता चलता है कि जब मृतक को गोली लगी, तो वह खड़ी स्थिति में रहा होगा और गोली शरीर के बाईं ओर से प्रवेश करके दाईं ओर से बाहर निकल गई होगी। हालाँकि, इस तथ्य की पुष्टि पीडब्लू 7 (गंभीर सिंह) और पीडब्लू 8 (शांति देवी) के साक्ष्यों से होती है, लेकिन पीडब्लू 9 (माधो सिंह) और पीडब्लू 11 (बीर सिंह) के बयान इसका समर्थन नहीं करते हैं। इसी प्रकार, डॉ. उपाध्याय (पीडब्लू 12) और प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों के बीच विरोधाभास थे कि मृतक को गंभीर चोट पहुंचाने के दौरान हमलावर की दूरी और ऊंचाई क्या थी और क्या मृतक मंच (चबूतरा) पर खड़ा था या गोली लगने के दौरान उससे नीचे आ गया। हमें डॉ. उपाध्याय (पीडब्लू 12) के बयान से पता चलता है कि वह यह बताने के लिए स्पष्ट और निश्चित नहीं थे कि हमलावर ने किस स्थिति और दूरी से बंदूक चलाई होगी।

21. जब्ती ज्ञापन (एक्स.पी /3) के अनुसार, जाहिर तौर पर अपीलकर्ता के पास से एक बंदूक, 12 जिंदा और 9 खाली कारतूस बरामद किए गए। प्रत्यक्षदर्शियों के साक्ष्य इस तथ्य का समर्थन करते हैं और बंदूक और कारतूस की बरामदगी के बाद आई.ओ. से कोई सवाल नहीं पूछा गया कि क्या उसने सबूत बनाने के लिए जब्त बंदूक से खुद गोली चलाई थी। अभियोजन पक्ष की कहानी कुछ हद तक बैलिस्टिक विशेषज्ञ की

रिपोर्ट (एक्स.पी /12) से मजबूत होती है जो पुष्टि करती है कि अपीलकर्ता से जब्त की गई बंदूक सही क्रम में थी, खाली कारतूसों पर पिन पर वही छाप थी जो आरोपी से जब्त की गई थी और जिंदा कारतूसों पर वास्तव में अपीलकर्ता से जब्त की गई बंदूक से गोली चलाई गई थी, परंतु कहीं भी यह उल्लेख नहीं किया गया कि पीड़ित की मृत्यु जब्त बंदूक से निकली गोली से हुई। केवल अपीलकर्ता से बंदूक और कारतूस की जब्ती, विभिन्न आपराधिक मुकदमों के कारण पक्षों के बीच चल रही दुश्मनी और एक ही दिन की सुबह प्रतिद्वंद्वी समूहों के बीच विवाद और गर्म शब्दों के आदान-प्रदान से आरोपी के अपराध को स्थापित नहीं किया जा सकता है।

22. ऐसे मामलों में जहां चिकित्सा साक्ष्य और चश्मदीद संबंधी साक्ष्य के बीच विरोधाभास है, कानून की स्थिति को इस आशय से स्पष्ट किया जा सकता है कि यद्यपि किसी गवाह की चश्मदीद संबंधी गवाही का साक्ष्य चिकित्सा साक्ष्य की तुलना में अधिक होता है, यह साक्ष्य के मूल्यांकन की प्रक्रिया में एक प्रासंगिक कारक बन जाता है। हालाँकि, जहाँ चिकित्सा साक्ष्य चश्मदीद संबंधी साक्ष्य के सत्य होने की सभी संभावनाओं को पूरी तरह से खारिज कर देता है, वहाँ चश्मदीद संबंधी साक्ष्य पर अविश्वास किया जा सकता है [देखें अब्दुल सईद बनाम एम.पी. राज्य, (2010) 10 एससीसी 259]

23. अभियोजन पक्ष के गवाहों के विरोधाभासी बयानों के साथ- साथ विवादित चिकित्सा साक्ष्य, आई.ओ. द्वारा गवाहों के बयान दर्ज करने में देरी, उचित स्थल योजना की अनुपलब्धता और प्रमाणित बैलिस्टिक विशेषज्ञ रिपोर्ट के अभाव में कि गोली अपीलार्थी की जब्त बंदूक से चलाई गई थी, विचारण न्यायालय को अभियोजन पक्ष के खिलाफ मामले का फैसला करना पड़ा और अभियोजन पक्ष को बरी करना पड़ा। उच्च न्यायालय ने साक्ष्य के पुनर्मूल्यांकन का अभ्यास करने पर यह विचार व्यक्त किया कि गवाहों के बयान दर्ज करने में देरी के कारणों को ठीक से समझाया गया है कि जैसे ही गोली मृतक के पेट पर लगी, वह तुरंत मंच से नीचे गिर गया। उल्लेखनीय है कि शांति देवी (पीडब्लू 8) के नाम का उल्लेख प्राथमिकी में नहीं किया गया था, लेकिन घटना के समय अन्य चश्मदीद गवाहों के साथ उनकी उपस्थिति को स्थापित करने के लिए रिकॉर्ड पर सकारात्मक सबूत हैं और यह तथ्य उनके संतोषजनक बयानों से स्थापित किया गया है और इसमें अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। यहाँ यह उल्लेख करना सार्थक है कि नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों ने एक आम राय बनाई कि अभियोजन पक्ष सह अभियुक्तों के खिलाफ आई. पी. सी. की धारा 148 और 302/149 के तहत आरोपों को साबित करने में विफल रहा है और उन्हें उन आरोपों से मुक्त कर दिया गया। विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय के बीच असहमति केवल अपीलकर्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत आरोप के संबंध में है।

24. शीर्ष अदालत का यह कर्तव्य है कि बयानों के शोरगुल से सच्चाई को बाहर निकाले। समय के अंतराल के कारण मनुष्यों के लिए अलग-अलग बयान देना स्वाभाविक है, लेकिन अगर ऐसे बयान अभियोजन के मूल को कमजोर करते हैं तो ऐसे विरोधाभास स्वाभाविक हैं और न्यायालय को ऐसे बयानों से सावधान रहना होगा [देखें तहसीलदार सिंह बनाम यू.पी. राज्य, ए.आई.आर. 1959 एससी 1012, पुधु राजा बनाम राज्य, (2012) 11 एससीसी 196, यू.पी. राज्य बनाम नरेश, (2011) 4 एससीसी 324]. मौजूदा मामला एक उपयुक्त मामला है, जिसमें स्वाभाविक अतिशयोक्ति और विरोधाभास हैं, जो अनिवार्य रूप से संदेह पैदा करता है जो सामान्य परिस्थितियों में उचित है और अभियोजन पक्ष के मामले के आधार को ध्यान में रखते हुए, हम उचित संदेह से परे यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं कि अपीलकर्ता मृतक की मौत का कारण बना।

25. आम तौर पर, जब कोई अपराधी हत्या जैसे जघन्य अपराध को अंजाम देता है और किसी इंसान की जान ले लेता है, यदि उस अपराधी को उचित सजा नहीं दी जाती है, तो न्यायालय अपने कर्तव्य में विफल होगा। ऐसा अपराध, जब किसी अपराधी द्वारा खुलेआम किया जाता है, अकेले किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं किया जाता है, बल्कि उस समाज के खिलाफ भी किया जाता है, जिसका अपराधी और पीड़ित हिस्सा होते हैं। इस न्यायालय को इस बात पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि ऐसे अपराध के लिए दी जाने वाली सजा प्रासंगिक होनी चाहिए और यह उस

अत्याचार और क्रूरता के अनुरूप होनी चाहिए जिसके साथ अपराध को अंजाम दिया गया है।

26. मौजूदा मामले में, इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक निर्दोष व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के हाथों अपनी जान गंवा दी है, और जिस तरह से जांच की गई, उसे देखकर हमें यकीन है कि यह लापरवाही से की गई थी। गवाहों के बयान दर्ज करने, साक्ष्य एकत्र करने और स्थल मानचित्र तैयार करने में जांच अधिकारी का रवैया लापरवाही भरा रहा। हत्या के मामले की जांच करने वाले जांच अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने दृष्टिकोण में मेहनती, सच्चा और निष्पक्ष हो और उसका प्रदर्शन हमेशा पुलिस मैनुअल के अनुरूप होना चाहिए और कर्तव्य में चूक या उल्लंघन अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक साबित हो सकता है। हम यह कहने में जल्दबाजी कर सकते हैं कि वर्तमान मामले में जांच असंबद्ध और प्रेरणाहीन प्रदर्शन के साथ की गई थी। अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए आवश्यक उत्साह और भावना के साथ कोई दृढ़ और ईमानदार प्रयास नहीं किया गया। हमारा मानना है कि उच्च न्यायालय के पास बरी करने के आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए कोई बाध्यकारी और ठोस कारण नहीं हैं, जब अभियोजन पक्ष अभियुक्त के अपराध को स्थापित करने में बुरी तरह विफल रहा है। इसके अलावा, आरोपी पहले ही नौ साल की सजा काट चुका है और हमें लगता है कि यह मामला इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप करने वाला एक उपयुक्त मामला है।

27. परिणामस्वरूप, अपील की अनुमति दी जाती है और उच्च न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि के फैसले और सजा के आदेश को रद्द कर दिया जाता है। परिणामस्वरूप, यदि किसी अन्य मामले में आवश्यक न हो तो अपीलकर्ता को तुरंत रिहा कर दिया जाएगा।

कल्पना के त्रिपाठी

अपील स्वीकार

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी शंकर लाल मारू (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।